राजनैतिक इच्छाशक्ति बगैर ग्राम स्वराज संभव नहीं

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

'...हमारे गांव के अध्यापक का नाम क्या है?' राजस्थान के एक गांव की साधारण महिला ने आरटीआई के जरिए एक सवाल पूछकर पूरे गांव को 10 साल से चली आ रही दिक्कत से छुटकारा दिला दिया। असल में एक राजनेता के सम्बन्धी होने पर अध्यापक ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। उसने मात्र पांच हजार रुपए पर अपनी जगह अस्थायी अध्यापक को रख लिया था। व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण और समाज के अंतिम व्यक्ति की जागरूकता से पूरे गांव को लाभ मिला। इसी उम्मीद पर 'जिला योजना के विकेन्द्रीकरण में मीडिया की भूमिका' विषय पर गुरुवार से लखनऊ के होटल जेमिनी में दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसमें वक्ताओं ने शहर व गांव के लोगों के जरिए योजनाएं बनाने पर बल दिया। इस उद्देश्य को पाने के लिए जनप्रतिधियों से राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की अपेक्षा की गई।

वरिष्ठ पत्रकार पी ठाकुरता गुहा ने कारपोरेट क्षेत्र का दखल बढ़ने के बावजूद मीडिया से अपना काम ईमानदारी से करने की अपील की। उन्होंने 'पेड न्यूज' की बुराई के बाद भी सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों को उठाने में मीडिया की सराहना की। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा ने मीडिया को 'अंत्योदय' (समाज के अंतिम व्यक्ति) के लिए अपनी जवाबदेही के प्रति आगाह भी किया।

सत्र का संचालन कर रहे बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी ने लोकतंत्र की खातिर सामाजिक मुद्दों को आगे लाने के लिए मीडिया प्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करने की अपील की।

कार्यशाला की आयोजक संस्था 'इनक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज' के निदेशक डा. विपुल मुद्गल ने कहा कि शिक्षा व सूचना का अधिकार अधिनियम बनने से व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की उम्मीदें बढ़ी हैं। उन्होंने मीडिया से ग्राम स्वराज के लिए सोशल ऑडिट व ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने की भी बात कही।

कार्यशाला में दिग्गजों ने दिया योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी पर जोर ● हिन्दुस्तान

'एफडीआई व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था साथ-साथ नहीं चल सकतीं'

● कार्यशाला में आए ए एन सिन्हा सोशल स्टडी इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रो. डी.एम. दिवाकर ने कटाक्ष किया कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में योजनाएं ग्राम स्तर पर बनाने और एफडीआई को मंजूरी देने से ग्राम स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको से विकसित होने का अर्थशास्त्र सीखना पड़ेगा।

इसी सत्र में पंचायतीराज की शीर्ष कमेटी के सदस्य एमएन रॉय ने ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने व ग्रामीण स्तर पर कर प्रणाली लागू कर पैसा एकत्र करने पर बल दिया। पहले सत्र का संचालन कर रहे 'हिन्दुस्तान' के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक नवीन जोशी ने कहा कि अगर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था सही ढंग से लागू होती तो एलडीए भी नगर निगम के अधीन होता। पार्षद व महापौर जनता के काम के लिए बजट का दुःखड़ा नहीं रोते।

इसके पहले उद्घाटन सत्र में पंचायती संस्थाओं की नोडल अफसर मृदुला सिंह ने केरल व अन्य प्रांतों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की गति काफी होने की बात स्वीकारी। मुख्य अतिथि नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव संजीव नायर ने गांवों को केरल की तरह स्वावलंबी बनाने की बात की।